







# संपादकीय

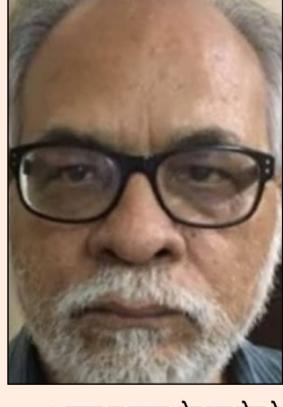
## काषू मे मलोरया

यह सुखद ह क पूरा दुनया म पछल दा दशक म मलारिया क खिलाफ जंग में आशातीत सफलता मिली है। जिससे जहां मलेरिया के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, वहीं मौत के आंकड़ों में कमी आई है। पिछले दिनों जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि सार्थक प्रयासों से भारत मलेरिया की दृष्टि से अधिक संवेदनशील देशों की सूची से बाहर निकल गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालिया रिपोर्ट में जिक्र किया है कि भारत में मलेरिया के मामलों में जहां 69 फीसदी की कमी आई है, वहीं इससे होने वाली मौतों में 68 फीसदी की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि देश के मलेरिया से ज्यादा प्रभावित राज्यों में सघन अभियान चलाया गया। साथ ही जागरूकता अभियान से भी इस दिशा में लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिली है। दरअसल, मलेरिया से ज्यादा प्रभावित राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में मलेरिया उन्मूलन अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। इसके चलते भारत को डब्ल्यूपीआर्ओ ने उन देशों में शुमार किया है जिन्होंने इस दिशा में आशातीत सफलता हासिल की है। सुखद यह है कि मलेरिया से अधिक प्रभावित देशों मसलन अप्रेकी देशों में नई वैक्सीन के ट्रायल के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि हर साल जो लाखों लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं, नई वैक्सीन के प्रभाव से उनकी जान के जोखिम को कम किए जाने में मदद मिल सकेंगी। दरअसल, वैक्सीन के फेज-2बी के क्लीनिकल ट्रायल के परिणाम बताते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में कारगर है। वैक्सीन की प्रभावशीलता पचपन फीसदी बतायी गई है। उल्लेखनीय है कि मशहूर चिकित्सा पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि वैक्सीन रक्त में मौजूद मलेरिया की वजह बनने वाले परजीवियों के खिलाफ प्रभावी पायी गई है। जिसे जीवन की रक्षा के लिये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है उल्लेखनीय है कि जहां भारत में वर्ष 2017 में मलेरिया के चौंसठ लाख मामले थे, वे वर्ष 2023 में घटकर बीस लाख रह गए। वहीं मलेरिया से होने वाली मौतों पर भी अंकुश लगा है। दरअसल, जागरूकता अभियान से उत्पन्न चेतना तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से मलेरिया उन्मूलन में खासी मदद मिली है। एक अनुमान के अनुसार कोई पौने दो करोड़ मलेरिया के मामलों को टाला गया है। वहीं मलेरिया जोखिम में भी आशातीत गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के आठ देश मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित थे। जिसमें भारत में भी स्थिति विगत में चुनौतीपूर्ण थी। दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात को लेकर चिंतित था कि इस क्षेत्र में सघन आबादी के चलते दुनिया की एक चौथाई आबादी निवास करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण एशिया के इन देशों में मच्छरों से पैदा होने

आज भीड़-प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि यह व्यापक स्तर पर

इनसानी मौता से जुड़ा मुद्दा है और उसके प्रति लापरवाही का रखेया रहा है। देश के कई हिस्सों में भीड़-प्रबंधन की नाकामी और नालायकी के कारण भगदड़ मचती रही है। अक्सर पुलिस की नाकामी करार दी जाती रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2014 में 95 पत्रों के दिशा-निर्देश जारी किए थे कि भीड़ को भगदड़ में तबदील होने से कैसे रोका जाए? इसी साल नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद भगदड़ में मचतीरही हैं। इसी साल जुलाई में हाथरस (उप्र) में एक धार्मिक सत्संग में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ में करीब 125 मौतें हो गई। सिर्फ आयोजकों को जेल में डाल कर घटना की इतिश्री कर दी गई। हाल ही में हैदराबाद में 'पुष्टा-2' फिल्म के प्रीमियर पर भीड़ अनियंत्रित हो गई, कुछ मौतें हो गईं, पुलिस ने अभिनेता अलू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। क्या भगदड़ का कारण यही था? दरअसल अंग्रेजी में जिस शब्द का अर्थ 'भगदड़' है, वह घोड़ों और पशुओं की भगदड़ है, जो डर कर या उत्तेजित होकर एक ही दिशा में भागने लगते हैं। तब भगदड़ मच जाती है। 'इनसानी भगदड़' कुछ और है, उसके कारण भी भिन्न हैं, उनके लिए यह बहाना नहीं बनाया जा सकता कि सरकार ने दिशा-निर्देश जारी नहीं किए अथवा पुलिस, प्रशासन को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया अथवा सरकार का रखेया संवेदनशील नहीं है।

राण्ड्र रामा क तान व्यवध



१. હણાણ વા ઝટફા- તાદ પવા હણા એ  
જનતત્ત્ર!

जन अज्ञान से हैं जो जान का काम करते हैं। लगाने में विश्वास करते हैं। जन न, जन इलेवनशन का ही देख लीजिए। मारी जी तो तो एक ही झटके में जन नेशन नो इलेवनशन सकते थे। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे! गोई उनका हाथ पकड़ने वाला। संसद में अच्छा-मा बहुत है। साधपति, गोई जी जहाँ कहें, वही र लगाने को तैयार है। न्यायालिका बहुत में न जाने चाहती है, जैसे तो जानती है। विरोध करने वालों के मुंह कराने के लिए इसी से लेकर सीबीआई, आईआई तक और नये राजद्रोह कानून से लेकर

गोटी में सरार है। और क्या चाहिए था। मगर नहीं किया। एक झटके में वन नेशन मैनी इलेवेशन से वन नेशन नो इलेवेशन नहीं किया। सिर्फ मैनी इलेवेशन से वन इलेवेशन किया, जिससे झटका भले जोर का हो, पर धीरे से लगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मोटी जी के न्यू डिड्या की प्रगति एक इलेवेशन पर ही रुक जाएगी। आएगा, वन नेशन नो इलेवेशन का भी नंबर आएगा। राम जी ने बाह, तो जल्द ही आएगा। पर तब तक वन नेशन में वन इलेवेशन। पहले ही कह, मोटी जी जोर का झटका धीरे से लगाने में विश्वास करते हैं। पैसे ऐसा भी नहीं है कि मोटी जी हमेशा झटका, धीरे से लगाने में ही विश्वास करते हैं। तब तो हलाका का मामला हो जाता किसी झटके से कम नहीं था। लखों मजूरों को पांच-पांच अपने गवां हौटोंने के लिए, बड़े-छोटे तमाम शहरों से बाहर धकेल दिया गया। यास्टे में पुलिस के डंडे खाए, सो ऊपर से। और तो और, रफाल मामले तक में मोटी जी ने सालों में हुए खटके के समझौते का झटका कर दिया और छोटे अंबानी के पुंछले बाला, अपना नाया सौदा आगे कर दिया। लेकिन, इस सब का मतलब यह भी नहीं है कि मोटी जी की जायदा प्रैविट्स झटका करने की ही है, कि वन नेशन वन इलेवेशन के मामले में पहली ही बार वह इसका ख्याल रख रहे हैं कि जोर का झटका धीरे से लगे। मोटी जी ने साथ चालाने-चालते शिर सेना के साथ क्या किया था? अकाली दल के साथ भी। और

ओर मोटी जी को मुसलमानों के साथ अपना नाम जोड़ा जाना जरा भी पसंद नहीं है। अद्वित, मोटी जी के राज में हलाल के सबसे बड़े विशेषी तो उग्र शाकाहारी हिंदू ही हैं। उनकी मानवाओं का आदर तो मोटी जी को भी करना ही पड़ता है। यानी मोटी जी झटके की तरह झटका करना भी खबरी जानते हैं, हलाकि वह खुद शुद्ध से भी शुद्ध शाकाहारी है। 2002 में गुजरात में वया हुआ था, गूढ़ गए वया ? गोधाया में ऐरेल के डिल्डों में आग लगाने के बाद, हृतों पूरे गुजरात में खुआ था, उसे हलाल तो किसी भी तरह से नहीं कह सकते हैं। या नोटर्डम में जो हुआ था, उसे ? था तो वह भी झटके का ही मानला। एक ही झटके में लोगों को बैंकों की लंबी-लंबी लाइनों में तेलुगु देशम के साथ। बांजु जनता दल के साथ। अंगिर सिंह के लोक दल के साथ। और तो और नीतीश बाबू के जट्यू के साथ भी। हलाल अंगर मुसलमानों के साथ चिपकने की वजह से वर्जित नीती हो गया होता, तो मोटी जी हलाल के भी मास्टर कहलाते। और हलाल का सलूक सिर्फ साथ घलने वाली राजनीतिक पार्टीयों तक ही सीमित नहीं था। कठीनी के मामले में तो मोटी जी ने एक के बाट एक, हलाल और झटका, दोनों ही आजमा डाले। पहले, मध्यबंग के साथ सरकार में बैटकट रखी डाल पर वीर-वीर आरी घालते रहे, जिस पर बैठे थे। और जब डाल करीब-करीब कर गयी तो, एकदम से डाल से नीचे कट गए। और गेहू बदलकर डाल को

दी जी का झटके का ही स्कोर ज्यादा है। मर्यादा, कनॉटक, मसाराट, उत्तराखण्ड आदि में विरोधी कारों के विधायक खारीट-खारीट के जो झटका है, उसे भी तो विदाव में लेना पड़ेगा। सच्ची तो यह है कि मोदी जी ने इस मामले में विषय वालों को पूरी तरह से कांपायूज कर के रखा हुआ है। और समझ ही नहीं पा रह है कि मोदी जी देश के सभी विधायिकाओं के साथ जो कर रहे हैं, उसे हलाल कहेंगे झटका। उन्हें कभी लगता है कि सविधान को बदल किया जा रहा है और कभी लगता है कि इसका किया जा रहा है। अलवित वन नेशन नो विधान से जाता, तो विज भी विषय वालों को कम कम कुछ बलेंटी तो मिल जाती कि संसदीय उत्तराखण्ड तो ब्रात दस्ती होगी।

जनतंत्र का ज़टका हो रहा है। लैकिन, उसने भी जी ने मामला वन इलेवशन पर अटका दिया। इसे संसदीय जनतंत्र का ज़टका होना, कहे भी कैसे कहें? अब तक कई धुनव थे, अब एक बचपन है; फिर भी चुनाव तो है! इसे जनतंत्र का ज़टका होना कहे भी तो कैसे? तो यह जनतंत्र का ज़टका होना भी एरी-एरी ही रेता जाएगा-हलाल! हलाल तोहफा लगवाना मोदी जी को हरिंग मंजूर नहीं होता। तभी तो वन इलेवशन में, लोटी जी ने एक ज़टके का भी रखा है। वन नेशन की तुक वन इलेवशन से बख्तरी गिलती तो है, पर वन इलेवशन ज्यादा जोर वन पर ही है, इलेवशन पर नहीं। एक बार वन इलेवशन की इंजिन तो होती, पर यह

दी है, एक पुनाव है, एक सरकार है, बसा दीरा क्या हर पांच साल पर बदलता है? नहीं जानी। तब हर पांच साल पर सरकार के लिए ही चुनाव कराया जाने की क्या जरूरत है? एक बार पुनाव हो गया, तो हो गया। एक बार सरकार चुन गयी, तो चुन गयी। यानी वन नेशन वन इलेक्शन वह पुल है, जिस से गुजर कर वन नेशन, नो इलेक्शन तक पहुंचा जाना है। यह वह पुल है, जिसके एक ओर सविधान का हाल किया जाना है और दूसरी ओर ड्रटका। यह पुल, हलाल और ड्रटके को जोड़ने वाला पुल है। यह पुल, सविधान, जनतंत्र, सब को बीच से तोड़ने वाला पुल है। यह पुल इसकी गारी का पुल है कि आज अगर सविधान को धीरे-धीरे खोला किया जा रहा है, तो कल उसे ड्रटके से तोड़ी भी दिया जाएगा। हाँ! अगर पलिक ही मोटी जी का खेल बिगाइने पर उत्तर आए, तो बाट दृश्य होगी।

2. इट इन बहुते डिफरेंट! याहिं कि बांगलादेश में तो हिन्दू अत्याधार हो रहे हैं, पर आलपसंस्कृत्यकों पर कोई अत्याधार रहे हैं। मान कि वर्हन-वर्हन लिमिट्जेंटेड-जर्जरों को खोदा जा बुलडोजर वरीहर चल रहे हैं, खाबन रहे हैं, पर अत्याधार...कठीन शब्दकोश ने अत्याधार का तो हिन्दुस्तान ने हिंदू जो कर रहे बांगलादेश में हिन्दुओं के साथ जो है। यह मुख्यतानान, वह हिंदू डिफरेंट!

समझ में खुदाई दूर हो रही है। शार्क सुरुदास से ज्यादा ढुकाई दूर हो रही है। आखिर, वहु तो मिलना चाहिए। अब बैचों लखनऊ और दिल्ली के ऊपर वाले भी वया कहें? खुदाई-खुदाई पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कम-से-कम अभी तो शोक लगा दी है। खुदाई छाड़िए, सुप्रीम कोर्ट वालों ने तो सर्व तक पर शोक लगा दी है। और सिर्फ संभल में ही नहीं, बाकी हट जगह भी सर्व तक के आदेशों पर तब तक के लिए शोक लगा दी है, जब तक बड़ी अदालत का अगला आदेश नहीं आ जाता है। सच पूछिए, तो शुरू-शुरू में तो संभल का प्रशासन नीं इस फरमान से कुछ हैलान-पेटेशन सा हो गया। थारी मासिजट तो मासिजट, उसके आस-पास के इलाके में भी, योगीशाही साथ-पांव संग्रह कर बैठ गयी। पर ज्यादा-से-ज्यादा दो दिन। तीसरे दिन तो बुलडोजर बाबा के बुलडोजरों ने बाकायदा नोर्म संभल ही लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ही एक और फैसले को धारा बताए हुए, जगीन से ऊपर दुकानों, मकानों वर्गेह पर बुलडोजरी खुदाई शुरू हो गयी। न्याय की देवी की अश्वों की पृष्ठ पहले ही खुल चुकी थी, सो बिना किसी मुश्किल से कपड़ों से पहवान-पहवान कर, मुसलमानों के दुकानों, मकानों पर, जगीन के ऊपर वाली बुलडोजरी खुदाई हुई। और जब बुलडोजर ही तैयार ने आ गया, फिर बाकी सरकारी अमला पीछे की ओर जात? जिलाधिकारी की लीडरशिप में थारी मासिजट के ईर्झ-गिर्झ के इलाके में अतिक्रमों की खुदाई शुरू हो गयी। इससे मन नहीं भया, तो मासिजट बैठवैह पर लाउडस्पीकरों की तलाशी शुरू हो गयी। उससे भी संतोष नहीं हुआ, तो फिरी तो भी नंदा-राज ने भी... अस्तित्व-







